SHIKSHA SAMVAD
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
© Shiksha Samvad|Volume-03| Issue-04| June- 2026
Available online at: https://shikshasamvad.com/
DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.07

महराजगंज के विकासखण्डों में शैक्षणिक सुविधाओं का असमान वितरण एवं उसके सामाजिक – आर्थिक प्रभाव

डॉ.अनुपमा सिंह

सहायक आचार्य , भूगोल विभाग, कामताप्रसाद सुन्दरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या(उत्तर प्रदेश)

सारांश –

यह अध्ययन महाराजगंज जनपद के विकासखण्डों में शैक्षणिक सुविधाओं के स्थानिक वितरण एवं उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विकासखण्ड स्तर पर विद्यालयों की उपलब्धता में विद्यमान असमानताओं की पहचान करना तथा उनके प्रभावों का मूल्यांकन करना है। इसके लिए भारत की जनगणना 2011 एवं उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जिनका वर्गीकरण, सारणीकरण एवं सरल सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से विश्लेषण किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनपद में शैक्षणिक सुविधाओं का वितरण असंतुलित है, जहाँ अनेक ग्राम विद्यालय-विहीन हैं तथा अधिकांश ग्रामों में शिक्षा की सुविधा केवल प्राथमिक स्तर तक सीमित है। उच्चतर स्तर के विद्यालयों की कमी के कारण विद्यार्थियों, विशेष रूप से ग्रामीण एवं बालिका वर्ग, की शिक्षा प्रभावित होती है। इस असमानता का प्रभाव साक्षरता दर, रोजगार के अवसर, आय स्तर एवं सामाजिक जागरूकता पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, जिससे क्षेत्रीय विकास में असंतुलन उत्पन्न होता है। अतः अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए शैक्षणिक अवसंरचना का समान एवं योजनाबद्ध विस्तार अत्यंत आवश्यक है। यह शोध नीति-निर्माताओं एवं योजनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जिससे वे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने हेतु प्रभावी रणनीतियाँ विकसित कर सकें।

कुंजी शब्दः शैक्षणिक असमानता, ग्रामीण शिक्षा , स्थानिक विश्लेषण , समाजिक – आर्थिक प्रभाव , महराजगंज जनपद ।

प्रस्तावनाः

महाराजगंज जनपद, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शिक्षा एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व के रूप में कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता न केवल साक्षरता दर को प्रभावित करती है, बल्कि यह मानव संसाधन विकास, रोजगार सृजन तथा जीवन स्तर में सुधार का आधार भी बनती है। तथापि, विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद में शैक्षणिक संस्थानों का वितरण समान नहीं है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के मध्य शैक्षिक अवसरों में असमानता उत्पन्न हो रही है।

विकासखण्डवार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुछ क्षेत्रो मे प्रथमिक , उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की पर्याप्त उपलब्धता है , जबकि अन्य क्षेत्रों में विद्यालयो का अभाव या सीमित उपस्थित देखी जाती है । विशेष रूप से अनेक ग्राम ऐसे हैं जहाँ कोई भी शैक्षणिक संस्था उपलब्ध नही है या

केवल प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा की सुविधा सीमित है। इस प्रकार की असमानता ग्रामीण छात्रों के शैक्षिक विकास को बाधित करती है तथा उच्च शिक्षा तक उनकी पहुँच को सीमित कर देती है , जिससे क्षेत्रीय विकास में असंतुलन उत्पन्न होता है।

शैक्षणिक सुविधाओं के इस असमान वितरण का समाजिक एवं आर्थिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पडता है। जिन क्षेत्रों में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नही है , वहाँ साक्षरता दर निम्न रहती है , बाल श्रम की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है तथा समाजिक जागरूकता का स्तर भी अपेक्षाकृत कम होता है। इसके विपरीत , जहाँ विद्यालयो की उपलब्धता अधिक है, वहाँ रोजगार के अवसर , स्वास्थ्य जागरूकता एवं समाजिक गतिशीलता में सकरात्मक परिर्वतन देखने को मिलता है। इस प्रकार शिक्षा का असमान वितरण समाजिक विषमताओं को और अधिक गहरा करता है।

अतः महराजगंज जनपद के विकासखण्डो में शैक्षणिक सुविधाओं के असमान वितरण का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है , जिससे न केवल क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान की जा सके , बल्कि उनके सामाजिक – आर्थिक प्रभावों का भी समुचित विश्लेषण किया जा सके। यह अध्ययन नीतिनिर्माताओ एवं योजनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा , जिससे वे शिक्षा के क्षेत्र में संतुलित एवं समावेशी विकास हेतु प्रभावी रणनीतियाँ तैयार कर सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक अवसरों की समानता सुनिश्चित कर सकें।

साहित्य समीक्षाः द्रेज एवं सेन (2013) ने भारत में शिक्षा और मानव विकास के मध्य सबंध का विश्लेषण करते हुए बताया कि शैक्षणिक सुविधाओं का असमान वितरण सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को बढाता है। उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी विकास प्रक्रिया को बाधित करती है तथा समावेशी नीतियों की आवश्यकता होती है।

तिलक (2007) ने शिक्षा के वित्तपोषित एवं उसके वितरण का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा में निवेश की असमानता क्षेत्रीय विकास में अंतर उत्पन्न करती है। उन्होने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक अवसंरचना को सुदृढ करने पर बल दिया।

प्रोब रिर्पोट(1999) में ग्रामीण भारत की प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए पाया गया कि विद्यालयों की उपलब्धता , संसाधनों की कमी तथा शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण शिक्षा का स्तर प्रभावित होता है। रिर्पोट ने क्षेत्रीय असमानताओं को प्रमुख समस्या के रूप में चिन्हित किया।

गोविंदा एवं बंद्योपाध्याय(2011) सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में शिक्षा की पहुँच का अध्यन करते हुए यह बताया कि शैक्षणिक संस्थानों का असमान वितरण विभिन्न समाजिक वर्गों के बीच शिक्षा में अंतर को बनाए रखता है।

सिह (2015) ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया और पाया कि विकासखण्ड स्तर पर विद्यालयों की उपलब्धता में स्पष्ट असमानता विद्दमान है, जो क्षेत्रीय विकास को प्रभावित करती है।

मेहरोत्रा (2006) के अनुसार शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, किन्तु जब शैक्षणिक सुविधाएँ समान रूप से उपलब्ध नही होती , तब समाज में आर्थिक एवं समाजिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। उन्होने शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

विश्व बैंक (2018) की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि विकासशील देशों मे शिक्षा का असमान वितरण गरीबी , बेरोजगारी एवं समाजिक बहिष्करण को बढाता है। रिर्पोट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार का विकास आवश्यक है।

भारत की जनगणना (2011) के आंकडो के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है , जो साक्षरता दर एवं समाजिक – आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। विशेष रूप से विकासखण्ड स्तर पर यह असमानता अधिक स्पष्ट होती है।

अध्ययन क्षेत्रः

महराजगंज जनपद उत्तर प्रदेश के उत्तर – पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिला है, जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल से सटी हुई है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र तराई एवं समतल मैदानों का संयुक्त स्वरूप प्रस्तुत करता है। जहाँ उपजाऊ जलोढ मिट्टी और कृषि- आधारित जीवन शैली

जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करती है। जनसंख्याकीय दृष्टि से यह जनपद राज्य में 34वें स्थान पर स्थित है तथा यहाँ का जनसंख्या घनत्व 910 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के औसत (829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) से अधिक है।

इस जनपद की नगरीकरण दर मात्र 5.0 प्रतिशत है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह मुख्यतः ग्रामीण एवं कृषि प्रधान क्षेत्र है। लिंगानुपात 943 है , जो राज्य के औसत 912 की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाता है। इसके विपरित, शैक्षिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है, जहाँ साक्षरता दर 62.8 प्रतिशत दर्ज की गई है,जो राज्य के औसत 67.7 प्रतिशत से कम है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले में कुल 1262 गाँव है , जिनमें से 50 गाँव निर्जन है, तथा यहाँ 7 नगरीय कस्बे स्थित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 के पश्चात कोई नया नगर शामिल नही किया गया , जो इस क्षेत्र में नगरीकरण की धीमी प्रगति को इंगित करता है।

इसके अतिरिक्त , जनसंख्या वृद्धि को प्रर्दशित करती है , जिसका प्रभाव संसाधनो के उपयोग , रोजगार , तथा आधारभूत सुविधाओं पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

मानचित्र संख्या: 01

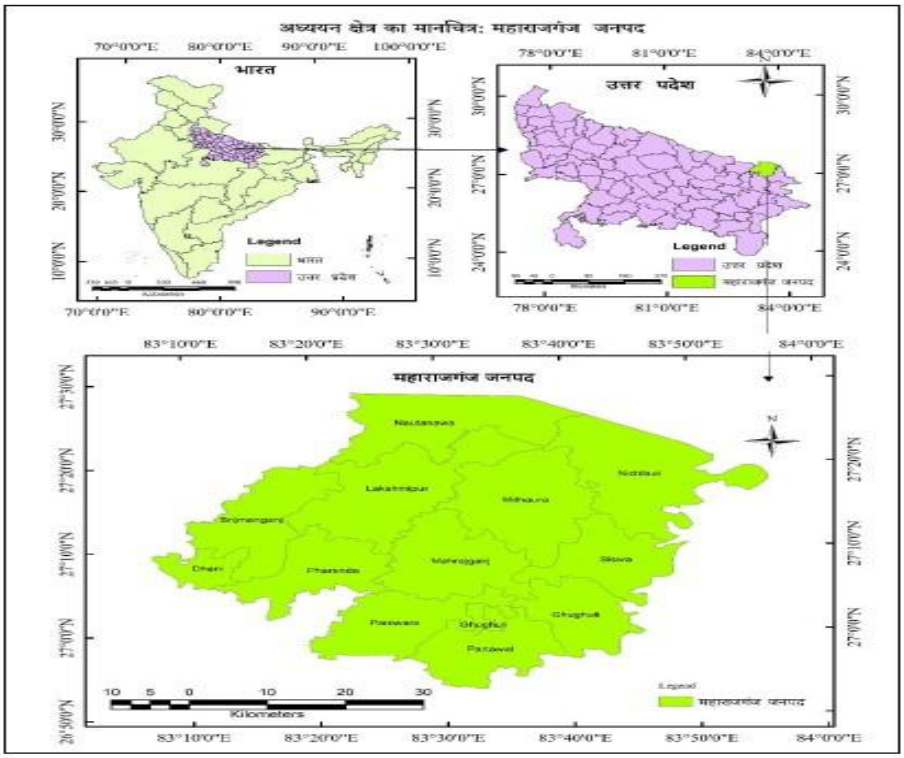

स्रोत: लेखक द्वारा, आर्क जीआईएस की मदद से तैयार मानचित्र।

उद्देश्यः

महराजगंज जनपद के विभिन्न विकासखण्डों में सुविधाओं के वितरण का अध्ययन करना।

शैक्षणिक सुविधाओं की असमानता के समाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना।

आंकडे एवं शोध विधि तंत्रः

इस अध्ययन में सरल एवं व्यावहारिक शोधविधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जिनमें भारत की जनगणना 2011 तथा महाराजगंज जनपद के विकासखण्डवार शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित आँकड़े सम्मिलित हैं। इन आँकड़ों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण कर विकासखण्ड स्तर पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। साथ ही, स्थानिक असमानता को समझने के लिए साधारण सांख्यिकीय विधियों जैसे प्रतिशत एवं अनुपात का उपयोग किया गया है। प्राप्त परिणामों के आधार पर शैक्षणिक सुविधाओं के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों की व्याख्या की गई है, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं की स्पष्ट समझ विकसित की जा सके।

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	कुल आजाद ग्रा	बिना विद्यालय	केवल प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
1	नौतनवा	121	10	37	71	16
2	लक्ष्मीपुर	142	37	52	52	8
3	निचलौल	161	41	60	56	12
4	मिठौरा	109	19	41	49	15
5	सिसवा	95	11	40	42	12
6	बृजमनगंज	93	17	27	49	18
7	धानी	34	15	5	14	4
8	फरेंदा	98	38	40	18	7
9	महराजगंज	85	10	34	41	7
10	घुघली	82	9	35	36	13
11	पनियरा	90	11	31	48	13
12	परतावल	102	30	35	37	9
योग		**1212**	**248**	**437**	**513**	**134**

परिणाम और चर्चा:

प्रस्तुत तालिका 01 के आधार पर महराजगंज जनपद के विकासखण्डों में शैक्षणिक सुविधाओं के वितरण का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि कुल 1212 आबाद ग्रामों में से 248 ग्राम ऐसे हैं जहाँ कोई भी विद्यालय उपलब्ध नहीं है, जो कुल ग्रामों का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अतिरिक्त 437 ग्रामों में केवल प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, जबकि 513 ग्रामों में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की सुविधा मौजूद है। वहीं मात्र 134 ग्रामों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर उच्च होता जाता है, वैसे-वैसे उसकी उपलब्धता में कमी आती जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संरचना की असंतुलित स्थिति को इंगित करती है।

विकासखण्ड स्तर पर विश्लेषण करने से क्षेत्रीय असमानताएँ और अधिक स्पष्ट होती हैं। निचलौल (41 ग्राम), लक्ष्मीपुर (37 ग्राम) तथा फरेंदा (38 ग्राम) जैसे विकासखण्डों में बिना विद्यालय वाले ग्रामों की संख्या अधिक है, जो इन क्षेत्रों में शैक्षणिक पिछड़ेपन को दर्शाता है। इसके विपरीत नौतनवा, महराजगंज एवं घुघली विकासखण्डों में बिना विद्यालय वाले ग्राम अपेक्षाकृत कम हैं, जो अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षणिक उपलब्धता को दर्शाता है। इसी प्रकार बृजमनगंज एवं मिठौरा में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता अन्य विकासखण्डों की तुलना में अधिक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुँच अपेक्षाकृत बेहतर है।

यदि शैक्षणिक सुविधाओं के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया जाए, तो यह पाया जाता है कि जिन विकासखण्डों में विद्यालयों की कमी है, वहाँ साक्षरता दर निम्न रहने की संभावना अधिक होती है, जिससे रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण जनसंख्या पारंपरिक एवं अल्प आय वाले कार्यों पर निर्भर रहती है, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। साथ ही, शिक्षा की कमी सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य स्तर एवं महिलाओं की भागीदारी को भी प्रभावित करती है, जिससे समग्र सामाजिक विकास बाधित होता है।

इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता अधिक है, वहाँ मानव संसाधन का विकास बेहतर होता है, जिससे रोजगार, आय स्तर एवं जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि महराजगंज जनपद में शैक्षणिक सुविधाओं का असमान वितरण क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को जन्म देता है। अतः आवश्यक है कि योजना निर्माण के दौरान उन विकासखण्डों पर विशेष ध्यान दिया जाए जहाँ शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव है, ताकि संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित किया जा सके।

© Shiksha Samvad | Received: 25 May-2026 | Accepted: 05 June - 2026 | Published: 08 June - 2026

शैक्षणिक सुविधाओं के स्तरानुसार वितरण का गहन विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश ग्रामों में शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक स्तर तक ही सीमित है। 437 ग्रामों में केवल प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता यह दर्शाती है कि उच्चतर शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को अन्य ग्रामों या कस्बों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह स्थिति विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करती है, क्योंकि दूरी एवं संसाधनों की कमी के कारण वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। परिणामस्वरूप, लैंगिक असमानता भी शैक्षणिक असमानता के साथ जुड़ जाती है, जो दीर्घकालीन सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है।

सुझाव:

महराजगंज जनपद के उन ग्रामों में जहाँ कोई विद्यालय उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित हो सके।

जिन विकासखण्डों में केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षा सीमित है, वहाँ माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु दूरस्थ क्षेत्रों पर निर्भर न रहना पड़े।

शैक्षणिक अवसंरचना के विकास के साथ-साथ योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों (भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि) की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु परिवहन सुविधा, छात्रवृत्ति एवं जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

योजना निर्माण के दौरान विकासखण्ड स्तर पर क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान में रखते हुए लक्षित नीतियां बनाई जानी चाहिए, ताकि शैक्षणिक सुविधाओं का संतुलित वितरण सुनिश्चित कर समावेशी सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

निष्कर्ष:

इस सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से सामने आता है कि महाराजगंज जनपद के विकासखण्डों में शैक्षणिक सुविधाओं का वितरण अत्यंत असमान एवं असंतुलित है, जहाँ एक ओर अनेक ग्राम ऐसे हैं जिनमें कोई भी विद्यालय उपलब्ध नहीं है, वहीं दूसरी ओर अधिकांश ग्रामों में शिक्षा की सुविधा केवल प्राथमिक स्तर तक सीमित है तथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की उपलब्धता अत्यंत सीमित पाई जाती है। विकासखण्ड स्तर पर भी उल्लेखनीय क्षेत्रीय विषमताएँ देखने को मिलती हैं, जैसे निचलौल, लक्ष्मीपुर एवं फरेंदा में शैक्षणिक सुविधाओं का अपेक्षाकृत अधिक अभाव, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इस असमान वितरण का प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक एवं आर्थिक संरचना पर पड़ता है, जहाँ शिक्षा की कमी के कारण साक्षरता दर निम्न रहती है, रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं, आय स्तर कम रहता है तथा गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन एवं लैंगिक असमानता जैसी समस्याएँ अधिक गहराती हैं। विशेष रूप से उच्च शिक्षा तक पहुँच के अभाव में ग्रामीण युवाओं एवं बालिकाओं के विकास के अवसर बाधित होते हैं, जिससे मानव संसाधन का समुचित विकास नहीं हो पाता। अतः यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि यदि महाराजगंज जनपद में संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है, तो शैक्षणिक अवसंरचना का समान एवं योजनाबद्ध विस्तार अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर उन विकासखण्डों में जहाँ शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव है, ताकि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक जागरूकता, आर्थिक प्रगति एवं जीवन स्तर में समग्र सुधार लाया जा सके।

संदर्भ सूची:

1. द्रेज़, जीन, एवं सेन, अमर्त्य. (2013). एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

2. तिलक, जे. बी. जी. (2007). फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NUEPA)।
3. प्रोब टीम. (1999). पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन इन इंडिया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. गोविंदा, आर., एवं बंधोपाध्याय, एम. (2011). एक्सेस टू एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया. NUEPA।
5. सिंह, ए. (2015). उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक विकास की क्षेत्रीय असमानताएँ। जर्नल ऑफ जियोग्राफी एंड रीजनल प्लानिंग, 8(4), 85–92।
6. मेहोत्रा, एस. (2006). रिफॉर्मिंग एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया. सेज पब्लिकेशन्स।
7. विश्व बैंक. (2018). वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट: लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन'स प्रॉमिस. वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन्स।
8. भारत सरकार. (2011). भारत की जनगणना 2011: प्राथमिक जनगणना सार (Primary Census Abstract). रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, भारत।
9. कुमार, ए., एवं शर्मा, आर. (2018). उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शिक्षा का क्षेत्रीय विश्लेषण। भारतीय भौगोलिक समीक्षा, 50(2), 120–132।
10. सिंह, पी., एवं यादव, एस. (2016). ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक अवसंरचना एवं विकास: एक अध्ययन। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 35(3), 45–60।
11. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2014). भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट. नई दिल्ली: एनसीईआरटी।
12. योजना आयोग. (2012). बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017): शिक्षा क्षेत्र. भारत सरकार।
13. अग्रवाल, एस. (2017). शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास के मध्य संबंध: एक भौगोलिक अध्ययन। भारतीय सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 42(1), 78–89।

Cite this Article:

डॉ.अनुपमा सिंह, "महराजगंज के विकासखण्डों में शैक्षणिक सुविधाओं का असमान वितरण एवं उसके सामाजिक – आर्थिक प्रभाव" Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 03, Issue 04, Pp.61-66, June-2026. Journal URL: https://shikshasamvad.com/

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ.अनुपमा सिंह

For publication of research paper title

महराजगंज के विकासखण्डों में शैक्षणिक सुविधाओं का असमान वितरण एवं उसके सामाजिक – आर्थिक प्रभाव

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03, Issue-04, Month June 2026.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://shikshasamvad.com/

DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.07